

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 681 / 2023 (धारा 14 शिक्वोरिटाईजेशन)
दि हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लॉट नं. के-14-18, सेक्टर 18, नोएडा।
प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री जय किशन शंकर लाल खण्डेलवाल,
पता- प्लॉट नं. 116, गुरु जाम्भेश्वर नगर-ए, क्वीन्स रोड, जयपुर
एवं जरिये हुवई टेलीकम्यूनिकेशन्स(इण्डिया) कम्पनी प्राईवेट लि. कार्यालय- एफ-1, 8th फ्लोर,
एवरशाईन टॉवर, आग्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर
एवं 1 202, दीपक बिल्डिंग सहारा स्टेट, लखनऊ, उत्तरप्रदेश।
2. श्रीमती सुनीता जय किशन खण्डेलवाल,
पता- प्लॉट नं. 116, गुरु जाम्भेश्वर नगर-ए, क्वीन्स रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री श्रेष्ठ माथुर, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

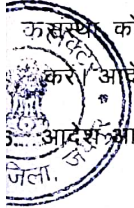
दिनांक: 30.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सुनीता खण्डेलवाल के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 116, गुरु जाम्भेश्वर नगर-ए, क्वीन्स रोड, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 320.52 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 27.02.2015 को राशि 51,39,000/- रूपये, दिनांक 25.09.2017 को राशि 79,70,000/- रूपये, कुल राशि 01,31,09,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

म
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 01,31,09,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 01,05,28,283.68/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.08.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सुनीता खण्डेलवाल के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 116, गुरु जाम्भेश्वर नगर-ए, क्वीन्स रोड, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 320.52 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पालन कर आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
- आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरीहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(मजिस्ट्रेट) जयपुर